Peoples Samachar (Indore) 19 January, 2017

## खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को संजीवनी देने व्यापक नीति की जरूरत

# खेतों से आपूर्ति 30 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता : एसोचैम

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
editor@peoplessamachar.co.in

अपार सम्भावनाओं से भरे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए केन्द्र सरकार को एक व्यापक खाद्य सुरक्षा योजना बनाने की जरूरत है। इस योजना में अन्तरराष्ट्रीय परिकल्पनाओं तथा दिशानिर्देशों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कृषि उत्पादों की आपूर्ति को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा सके। एसोचैम-टारी के संयुक्त अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है।

द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया (एसोचैम) और थॉट आर्बिटरेज रिसर्च इंस्टीट्यूट (टारी) द्वारा किए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगः मेक इन इंडिया में योगदान विषयक अध्ययन में रेखांकित करते हुए कहा गया है कि अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने, रसद के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने और

### खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

- इस उद्योग की मांग में बढ़ोत्तरी होने से अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण फल में तीन गुना तक वृद्धि हो सकती है।
- उद्योग की मांग में एक रुपये की वृद्धि होने पर अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों के सृजन में मोटे तौर पर 17 गुना और कृषि क्षेत्र में 15 गुना की वृद्धि होती है।
- निर्यात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का पांचवां स्थान है और वर्ष 2014-15 में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका योगदान 1.6 प्रतिशत का था।
- फैक्ट्रियों की संख्या (लगभग 16 प्रतिशत) और रोजगार के अवसरों (लगभग 16 प्रतिशत) के मामले में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शीर्ष पर है।

प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहयोग देकर श्रमिकों की क्षमता बढ़ाने से भारत को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का हब बनाने में खासी मदद मिलेगी।

एसोचैम के राष्ट्रीय महासचिव डी. एस. रावत और टारी की निदेशक सुश्री क्षमा कौशिक ने बुधवार को यहां इंदौर में संयुक्त रूप से इस ताजा अध्ययन की रिपोर्ट जारी की। अध्ययन में रेखांकित करते हुए कहा गया है कि बड़े कृषि संसाधन आधार के साथ-साथ श्रमिकों को सस्ता पारिश्रमिक, कच्चे माल की उपलब्धता से नजदीकी वाली जगह, संगठित खुदरा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि, सरकारी नीतियों पर सही अमल, बढ़ता शहरीकरण और बढ़ती हुई प्रतिव्यक्ति आय के कारण पैकेज्ड भोजन को दी जाने वाली तरजीह इत्यादि ऐसे कारक हैं जो भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देते हैं।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास की राह में अनेक रोड़े हैं। इनमें कृषि उत्पादों की निम्न और अनिरंतरता भरी गुणवत्ता, आमतौर पर खण्डित कृषि-आपूर्ति श्रंखला, कृषि-प्रसंस्करण के पुरातन तौर-तरीके, अकुशल श्रमशक्ति, अपर्याप्त मूलभूत ढांचा और निर्यात में प्रतिस्पर्द्धा की कमी इत्यादि ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं, जो भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की प्रगति में बाधक हैं।

### सोयाबीन और दालों के उत्पादन में अग्रणी प्रदेश

मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन (60 प्रतिशत) तथा दालों (27 प्रतिशत) का सबसे बड़ा उत्पादक है और पीली सरसों तथा काली सरसों (11 प्रतिशत) उत्पादन के मामले में दूसरी

### मध्य प्रदेश होगा भावी नेतृत्वकर्ता

अध्ययन में यह भी कहा गया है कि मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला मध्य प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकता है, और वह भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में व्यापक योगदान दे सकता है। हालांकि यह चिंताजनक विषय है कि 2015-16 में मध्य प्रदेश द्वारा आकर्षित करीब छह लाख करोड़ रुपए के कुल अदत्त निवेश में से खाद्य एवं कृषि आधारित उत्पाद का योगदान केवल 3382 करोड़ रुपए का ही रहा।

पायदान पर होने के साथ-साथ वह गेहूं उत्पादन (60 प्रतिशत) के मामले में भी तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश को अनाज और तेल उत्पादक बीज आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कुल उत्पादन का करीब आधा हिस्सा अनाज और तेल उत्पादक बीजों का ही होता है।